मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित
उत्तरशक्ति
हिन्दी दैनिक
हर खबर निष्पक्षता के साथ
मुंबई
वर्ष: 8 अंक 294
गुरुवार, 14 मई 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

भदोही में मौत बनकर उतरी आंधी, 18 मिनट और उजड़ गए 15 घर

भदोही। जिलेभर में बुधवार की शाम ऐसा मंजर देखा, जिसने जिले को दहला दिया। दिनभर की भीषण गर्मी के बाद लोग राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाम साढ़े पांच बजे आसमान से राहत नहीं, मौत उतरी। देखते ही देखते तेज हवाओं ने विकराल रूप ले लिया। करीब 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली आंधी ने महज 18 मिनट में पूरे जिले को तबाही के मलबे में बदल दिया। कहीं विशाल पेड़ धराशायी हुए, कहीं दीवारें भरभराकर गिर पड़ीं, तो कहीं बिजली के पोल लोगों पर मौत बनकर टूट पड़े। चीख-पुकार, अंधेरा और अफरा-तफरी के बीच जिलेभर में 15 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

सबसे दर्दनाक तस्वीर सुरियावां क्षेत्र के अभोली ब्लॉक स्थित खड़गसेन गोकुलपट्टी गांव से सामने आई। तेज आंधी के दौरान अचानक एक भारी पेड़ परिवार पर आ गिरा। हादसे में अशोक कुमार की पत्नी सुधा और उनकी तीन मासूम बेटियां – आरुषि, आरुही और जूही – हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गईं। घर का आठ वर्षीय आदर्श जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसे गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। गांव में जब एक साथ चार शव घर पहुंचे तो हर आंख नम हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा।

दुगार्गंज थाना क्षेत्र के रामपुर हरनाम गांव में राम हौसला बिंद घर के बाहर छप्पर के नीचे बैठे थे। अचानक आम का विशाल पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ा। लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर सुरियावां के झींगतपुर में मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ रहे शमसुद्दीन पर दीवार गिर गई। इबादत के बीच आई मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया।भदोही शहर के जमुंद मोहल्ले में आसमा बेगम छत

◆80 किमी की रफ्तार से चली हवाओं ने मचाई तबाही, पेड़-दीवार-पोल बने काल; मासूम बेटियों समेत एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

पर कपड़े उतारने गई थीं। तेज हवाओं के दबाव से दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और वह मलबे में दब गईं। चौरी थाना क्षेत्र के चांदी गहना गांव में 10 वर्षीय विवेक गौंड बिजली का पोल गिरने की चपेट में आ गया। गोपीगंज के कुलमनपुर गांव में 80 वर्षीय सवारी देवी घर के बाहर बैठी थीं, तभी नीम का पेड़ उन पर गिर पड़ा। औराई क्षेत्र के सरौली गांव में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गई तीन महिलाओं – लालती देवी, गीता देवी और राजकुमारी यादव – की पेड़ गिरने से मौत हो गई।आंधी का असर केवल जनहानि तक सीमित नहीं रहा। जिलेभर में 70 से अधिक पेड़ उखड़ गए। दर्जनों बिजली के खंभे टूट गए। कई हाईटेंशन टॉवर जमीन पर आ गिरे। पूरा जिला अंधेरे में डूब गया। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के ऊपर लगा 25 हजार वोल्ट का विद्युत तार नीम का पेड़ गिरने से टूट गया। कई ट्रेनें रास्ते में रोकनी पड़ीं। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। रामपुर घाट और नेवढ़िया के पीपा पुल भी तेज हवाओं की चपेट में आकर बह गए। गांवों का संपर्क टूट गया।

विशेषज्ञों के अनुसार बीते दो दिनों में तापमान में अचानक वृद्धि और वायुमंडलीय दबाव में बदलाव के कारण यह तूफानी स्थिति बनी। गर्म हवाओं और नमी के टकराव ने आंधी को खतरनाक रूप दे दिया। हालांकि तूफान कुछ मिनटों में गुजर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया मातम, उजड़े घर और दर्द से भरी चीखें। भदोही की यह शाम अब सिर्फ मौसम की घटना नहीं, बल्कि उन परिवारों की जिंदगी का सबसे भयावह अध्याय बन चुकी है।

पुडुचेरी के नए सीएम बने एन रंगास्वामी

पुडुचेरी, 13 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एन रंगास्वामी को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी और कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं।वएक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने रंगास्वामी के प्रशासनिक अनुभव और पुडुचेरी की विकास यात्रा में उनके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, श्री एन. रंगास्वामी को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई। अपने विशाल अनुभव के साथ, उन्होंने एक सक्षम प्रशासक के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी है, जिन्होंने पुडुचेरी की विकास यात्रा को मजबूत किया है। मैं लोगों के कल्याण के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि उनका कार्यकाल बेहतरीन रहे।

इससे पहले दिन में ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस के संस्थापक एन.

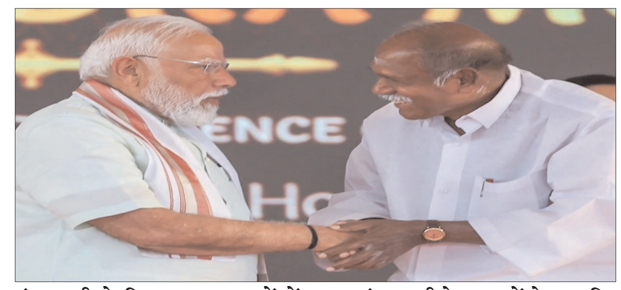

रंगास्वामी ने विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने इखढ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पदभार संभालने के तुरंत बाद, रंगास्वामी ने पुडुचेरी की जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि नई बनी एनडीए सरकार कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम करेगी।

रंगास्वामी ने पत्रकारों से कहा कि लोगों के कल्याण के लिए सभी जरूरी योजनाओं को और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम निश्चित रूप से इस ज़िम्मेदारी को पूरी उत्कृष्टता के साथ निभाएंगे।

उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए अपना दृष्टिकोण भी व्यक्त किया और कहा कि हम अपने पुडुचेरी को सिंगापुर की तरह विकसित करने जा रहे हैं। 4 मई को पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी।

रिजल्ट आया तो खिल उठी काशी, मेधावियों ने मचाया धमाल

●टॉपर्स की चमक से जगमगाई काशी, सीबीएससी रिजल्ट में सनबीम का परचम
●1291 विद्यार्थियों ने रचा सफलता का इतिहास, 334 छात्रों ने पाए शतक, दीया ने 98.4% से किया कमाल. अग्रिमा, अर्णव और मनस्वी बने सफलता के नए सितारे

वाराणसी। सीबीएसई कक्षा-12 के परीक्षा परिणामों में इस बार भी वाराणसी के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सनबीम शिक्षण समूह ने अपनी उत्कृष्टता का परचम लहरा दिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सनबीम समूह के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल विद्यालय बल्कि पूरे पूर्वांचल का

मान बढ़ाया। परिणाम घोषित होते ही भगवानपुर, लहरतारा, वरुणा, सनसिटी और सारनाथ शाखाओं में जश्न का माहौल बन गया। कहीं मिठाइयां बांटी गईं तो कहीं विद्यार्थियों ने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ अपनी सफलता का उत्सव मनाया।

इस वर्ष सनबीम समूह की पांचों शाखाओं से कुल 1291 छात्र-छात्राएं सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सभी विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त करते हुए 100 प्रतिशत परिणाम दर्ज कराया। इतना ही नहीं, 334 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया।

परिणामों की श्रेष्ठता सूची में सबसे ऊपर नाम रहा सनबीम लहरतारा की छात्रा दीया जीवनानी का, जिन्होंने मानविकी वर्ग में 98.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं सनबीम वरुणा की अग्रिमा चौबे ने 98.2 प्रतिशत, भगवानपुर की ऐश्वर्या खरे ने 97.4 प्रतिशत, सनसिटी के क्षितिज कुमार और सारनाथ की अदिति सिंह ने 96.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।

बाहुबली विजय मिश्रा को कठोर उम्रकैद, अदालत ने कहा – कानून की पकड़ से बच नहीं सकता अपराध का साम्राज्य

सुरेश गांधी

प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की बाहुबली राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल रहे पूर्व विधायक विजय मिश्रा के आपराधिक साम्राज्य पर अंतिम न्यायिक प्रहार कर दिया। 46 वर्ष पुराने प्रकाश नारायण पांडेय हत्याकांड में कोर्ट ने विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, न्याय की चौखट पर अंततः उसे झुकना ही पड़ता है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय की अदालत ने 11 फरवरी 1980 को इलाहाबाद कचहरी परिसर में हुई

46 साल बाद कचहरी के खूनी खेल का हिसाब

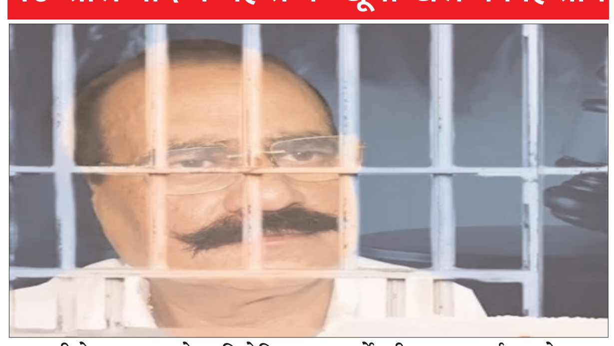

सनसनीखेज हत्या को सुनियोजित अपराध मानते हुए पूर्व विधायक विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम को दोषी करार दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सभी को कठोर उम्रकैद तथा एक-एक लाख रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई। इसके साथ ही धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष की अतिरिक्त कैद और 50-50 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया। यह फैसला केवल एक हत्या के मुकदमे का निर्णय नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में दशकों तक राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर न्यायपालिका की ऐतिहासिक टिप्पणी माना जा रहा है। 11 फरवरी 1980 को इलाहाबाद जिला अदालत परिसर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश नारायण पांडेय जमानत संबंधी कार्यवाही के लिए कचहरी पहुंचे थे। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते विजय मिश्रा और उसके साथियों ने कचहरी परिसर में ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस दौर में अदालत परिसर में हुई इस दुस्साहसिक हत्या ने पूरे प्रदेश को दहला दिया था। मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन न्याय की राह इतनी लंबी होगी, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में आरोपियों को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास हुए।

मुकदमे की पत्रावलियां तक गायब कर दी गईं। वर्षों तक केस अदालतों में उलझा रहा। गवाहों पर दबाव की चर्चा होती रही। राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल के दम पर मामला लगातार कमजोर करने की कोशिशें हुईं। लेकिन अंततः अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और न्यायालय की निगरानी में यह मुकदमा अपने निर्णायक मोड़ तक पहुंचा।

ट्रंप के चीन पहुंचने से पहले जिनपिंग ने दिखाए तेवर, कहा-ये चार लाल रेखाएं पार मत करना

चीन, 13 मई। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले साफ संदेश देते हुए कहा है कि दोनों देशों के संबंधों में मौजूद चार लाल रेखाओं को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि चीन-अमेरिका संबंधों में कुछ मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं और उन्हें पार नहीं किया जाना चाहिए। बीजिंग ने जिन चार मुद्दों को लाल रेखा बताया है, उनमें ताइवान का प्रश्न, लोकतंत्र और मानवाधिकार, राजनीतिक व्यवस्था और चीन के विकास का अधिकार शामिल हैं।

चीनी दूतावास ने यह भी कहा कि दोनों देशों को आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि वह चीन यात्रा के दौरान व्यापार और आर्थिक सहयोग पर विशेष जोर देंगे। ट्रंप ने बताया कि कई बड़े अमेरिकी उद्योगपति भी उनके साथ चीन जा रहे हैं। इनमें एलोन मस्क, टिम कुक और जेन्सेन हुआंग जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीन के बाजार को और खोलने की मांग करेंगे ताकि अमेरिकी कंपनियों को अधिक अवसर मिल सकें।

उन्होंने शी को बेहद प्रभावशाली नेता बताते हुए कहा कि यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और उत्साहजनक रहने वाली है।

ईरान मुद्दे पर भी ट्रंप ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि ईरान सैन्य रूप से कमजोर पड़ चुका है और या तो समझौता करेगा या फिर अमेरिका कार्रवाई पूरी करेगा।

पीएम मोदी ने गैस संकट को दूर करने के लिए उठाया बड़ा कदम, देश में अब कोयले से बनेगी गैस

नई दिल्ली, 13 मई। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों और गैस आपूर्ति को लेकर पैदा हो रहे संकट के बीच मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए देश के विशाल कोयला भंडार को ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोयले से गैस बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गयी। सरकार का मानना है कि अगले चार से पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर कोयले से गैस का उत्पादन शुरू होने पर भारत गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा और उसे वर्तमान जैसी वैश्विक आपूर्ति चुनौतियों तथा आयात निर्भरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज लिये गये फैसलों की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने

सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये 37 हजार 500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को गति देना है। इसके तहत लगभग 7 करोड़ 50 लाख टन कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और एलएनजी, यूरिया, अमोनिया तथा मेथनाल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी। योजना के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जायेगा। किसी एक परियोजना के लिये पांच हजार करोड़ रुपये तक की सीमा तय की गयी है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि गैसीकरण परियोजनाओं के लिये कोयला आपूर्ति अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष किया जायेगा ताकि निवेशकों को दीर्घकालिक स्थिरता मिल सके।

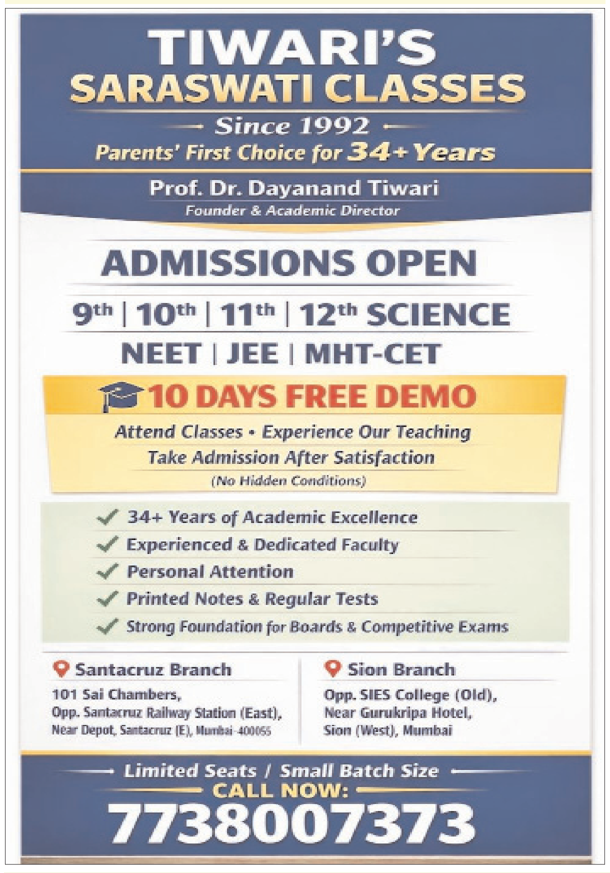

मोदी के राष्ट्रहित के आह्वान में भी राजनीति क्यों?

-ललित गर्ग

आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं ने मानव सभ्यता को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। खाड़ी देशों में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और युद्ध की विभीषिका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे तक प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं का बाधित होना, डॉलर के मुकाबले विभिन्न देशों की मुद्राओं का कमजोर होना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न असंतुलन ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और सोने का भी विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने की खरीद को सीमित करने का आह्वान केवल एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किया गया दूरदर्शी चिंतन है। दुर्भाग्य यह है कि मोदी की मितव्ययिता की अपील पर पूरे देश को एकजुट होकर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, उस विषय को भी राजनीतिक विवाद का हथियार बना दिया गया। कुछ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की इस अपील को जनता में भय फैलाने वाला कदम बताया, तो कुछ ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास कहा। जबकि वस्तुतः यह अपील राष्ट्र को भविष्य की संभावित चुनौतियों के प्रति सचेत करने और समय रहते आत्मानुशासन अपनाने का संदेश है। यह राजनीति का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी का प्रश्न है। जब विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र आर्थिक संकटों से जूझ रहे हों, तब भारत के प्रधानमंत्री यदि नागरिकों को संयम एवं मितव्ययिता का सूत्र देते हैं तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह पहला अवसर नहीं है, जब प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की को बनाए रखने की सामूहिक चिन्ता करते हुए मितव्ययिता एवं संयम की अपील की हो।

भारत की संस्कृति मूलतः संयम प्रधान रही है। भारतीय जीवन-दर्शन में संयम को केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। हमारे ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने सदैव आवश्यकता और विलासिता के बीच अंतर करना सिखाया। महावीर, बुद्ध, गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने त्याग और संयम को ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भारतीय संस्कृति कहती है कि जितना आवश्यक हो उतना ही उपभोग करो, क्योंकि असीमित उपभोग अंततः संकट को जन्म देता है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों तक टिकाऊ और संतुलित बनी रही। आज जब पूरी दुनिया उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम भुगत रही है, तब भारत की यही संयम आधारित संस्कृति समाधान का मार्ग दिखा सकती है। सोने के प्रति भारतीय समाज का आकर्षण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरा रहा है। विवाह, पारिवारिक उत्सव, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक प्रतिष्ठा में सोने का विशेष स्थान है। लेकिन यह भी एक कठोर सत्य है कि भारत का अधिकांश सोना आयातित होता है। हर वर्ष अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सोने के आयात पर खर्च होता है। यह सोना उत्पादन या औद्योगिक विकास में उपयोग होने के बजाय घरों और लॉकरों में बंद होकर निष्क्रिय पड़ा रहता है। ऐसे समय में जब विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा हो और रुपये की कीमत लगातार गिर रही हो, तब सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। यह किसी की परंपराओं के विरोध में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती के पक्ष में उठाया गया कदम है।

इसी प्रकार ईंधन के उपयोग में संयम भी समय की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ता है। यदि नागरिक ईंधन के अनावश्यक उपयोग को सीमित करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, ऊर्जा बचत को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। संयम का अर्थ केवल त्याग नहीं होता, बल्कि दूरदर्शिता और जिम्मेदारी भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील इसी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। उन्होंने किसी प्रकार की जबरदस्ती या प्रतिबंध की बात नहीं की, बल्कि नागरिकों से स्वैच्छिक सहयोग की अपेक्षा की। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व की पहचान है। एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का कर्तव्य केवल संकट आने पर कदम उठाना नहीं होता, बल्कि संकट के संकेतों को पहचानकर समय रहते जनता को तैयार करना भी होता है। आज जब दुनिया के कई देशों में आर्थिक अस्थिरता के कारण भारी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव देखने को मिल रहे हैं, तब भारत अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में अपनाई गई आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति का परिणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वव्यापी संकटों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। महामारी से लेकर युद्धजनित परिस्थितियों तक भारत सरकार ने लगातार राहत योजनाएं चलाईं, गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, किसानों और मध्यम वर्ग को विभिन्न प्रकार की सहायता दी तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए। वैश्विक मंदी और युद्ध के वातावरण में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण है।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देशहित के ऐसे विषयों पर भी कुछ राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन हर विषय को राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू में तौलना राष्ट्रहित के विरुद्ध है। यदि प्रधानमंत्री जनता से संयम की अपील करते हैं तो विपक्ष को चाहिए कि वह भी जनता को जागरूक करे, न कि भय और भ्रम का वातावरण बनाए। राजनीति तब तक स्वस्थ मानी जाती है जब तक वह राष्ट्रहित से जुड़ी रहे। लेकिन जब राजनीति केवल विरोध के लिए विरोध करने लगे और राष्ट्रीय संकटों को भी अवसर की तरह देखने लगे, तब वह लोकतंत्र को कमजोर करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरा देश एक परिवार की तरह सोचते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माने। संकट के समय संयम, अनुशासन और सहयोग ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। भारत ने इतिहास में अनेक बार यह सिद्ध किया है कि जब भी राष्ट्र पर संकट आया, भारतीय समाज ने अद्भुत त्याग और एकता का परिचय दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर युद्धकाल तक, भारतीय जनता ने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को महत्व दिया है। आज फिर वही समय है जब हमें समझना होगा कि अनावश्यक उपभोग, दिखावे की प्रवृत्ति और अंधाधुंध विलासिता अंततः देश की आर्थिक मजबूती को कमजोर करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। यह केवल सोना न खरीदने या ईंधन बचाने का संदेश नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आत्मअनुशासन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का संदेश है। भारतीय संस्कृति का मूल स्वर भी यही रहा है कि व्यक्ति अपने आचरण से समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाए। यदि हम संयम को जीवन का हिस्सा बना लें तो अनेक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान स्वतः संभव हो सकता है। आज दुनिया जिस अनिश्चितता और संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसका श्रेय देश की जनता की सामर्थ्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी जाता है। ऐसे समय में आवश्यकता राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सकारात्मक सोच की है। संयम केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का आधार है। यदि हम इस भावना को समझ सकें, तो न केवल वर्तमान संकटों का सामना कर पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकेंगे।

राहुल-प्रियंकाः देश के प्रति योगदान जीरो फिर भी मीडिया के हीरो

-संजय सक्सेना

एक समय था जब भारतीय राजनीति में कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार की जड़ें समान रूप से काफी मजबूत हुआ करती थीं। लोग तो यहां तक कहते थे कि नेहरू-गांधी परिवार के बिना कांग्रेस अधूरी मानी जाती थी। कांग्रेस ने देश को जितने प्रधानमंत्री दिए, उनमें इस परिवार के तीन सदस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ने कुल मिलाकर कई दशक तक देश पर राज किया। कांग्रेस तब तक उभार पर रही, जब तक पार्टी के भीतर इन तीनों का सिक्का चला, लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर आने के बाद धीरे-धीरे कांग्रेस का बुरा दौर शुरू हो गया। हालांकि यह इतना बुरा भी नहीं था कि कांग्रेस हाशिये पर चली गई हो। 2014 तक वह किसी न किसी तरह सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हो ही जाती थी, परंतु जब से सोनिया गांधी की पकड़ पार्टी पर कमजोर और राहुल गांधी की मजबूत होना शुरू हुई, तब से कांग्रेस का बेहद बुरा दौर आ गया। केंद्र की सत्ता तो कांग्रेस से फिसली ही, राज्य दर राज्य भी कांग्रेस की सरकारें जाती रहीं। हालात यह हो गया कि नेशनल पार्टी का तमगा हासिल किए हुए कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनकर रह गई। यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है। यहां भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को अपनी इच्छानुसार सीटें दी थीं। हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के सहारे सत्ता में आई है।

कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बनने का दौर राहुल गांधी के समय ही शुरू हुआ था। कांग्रेस के खोते जनाधार और गिरते मनोबल को बचाने में जब राहुल गांधी कामयाब होते नहीं दिखे, तो प्रियंका वाड्रा को भी कांग्रेस का ट्रंप कार्ड बताते हुए मैदान में उतार दिया गया, लेकिन उनका भी जादू चल नहीं पाया। भाई-बहन की जोड़ी भी कांग्रेस की तस्वीर नहीं बदल पाई। यह और बात है कि आज भी कांग्रेस को अर्श से फर्श पर ला देने वाले राहुल गांधी की ही पार्टी के भीतर तूती बोलती है। कांग्रेस का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता राहुल-प्रियंका के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है, जबकि राहुल के कई फैसले पार्टी के लिए घातक साबित हो चुके हैं।बहरहाल, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज की तारीख तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी का देश और पार्टी को आगे ले जाने में किसी तरह का कोई खास योगदान नहीं है। पार्टी के लिए इन दोनों ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, जिससे कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही हो। इसके उलट कांग्रेस लगातार जनाधार खोती जा रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस के पतन के लिये जिम्मेदार राहुल गांधी और प्रियंका को भारतीय मीडिया इतना हाईलाइट क्यों करता है, जबकि देश-विदेश में भारत की छवि दागदार करने, राहुल के देश विरोधी ट्वीट और हिंदू विरोधी छवि के कारण जनता इन्हें लगातार नकारती जा रही है। आश्चर्य होता है कि क्यों मीडिया की दुनिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आज भी प्रमुखता से चमकता रहता है। यह सवाल भारतीय राजनीति और मीडिया के गठजोड़ की उस जटिल गुत्थी को खोलता है, जहां वोट की बजाय व्यूअरशिप और एडवर्टाइजमेंट राज करता है। गहराई से विश्लेषण करें तो पता चल जाता है कि कैसे ये दोनों नेहरू-गांधी परिवार के वारिस बनकर राजनीति में बने हुए हैं।

दरअसल, राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा शुरू से ही विवादों और असफलताओं से भरी रही। 2004 में अमेठी से सांसद बने, फिर 2014 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रियंका गांधी ने 2019 में महासचिव बनकर पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाला, लेकिन 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटें मिलीं। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें जरूर मिलीं, लेकिन यह राहुल या प्रियंका के व्यक्तिगत करिश्मे से कम, गठबंधन और मोदी विरोधी माहौल से ज्यादा जुड़ा रहा। आंकड़े साफ कहते हैं कि 2014 में कांग्रेस के पास 44 लोकसभा सीटें थी, 2019 में 52, लेकिन राज्य स्तर पर हाहाकार मचा रहा। यूपी में 403 सीटों वाली विधानसभा में 2022 में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलीं, पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी 92 से घटकर 18 सीटों पर पहुंच गई। हिमाचल में भले कांग्रेस जीती, लेकिन गुजरात में 156 में से केवल 1 सीट मिली। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इन दोनों का नेतृत्व पार्टी को मजबूत बनाने में नाकाम रहा। जनाधार का सिकुड़ना भी छिपा हुआ नहीं है। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर 19.5 फीसदी था, 2019 में 19.3 फीसदी, जबकि बीजेपी 38 फीसदी से ऊपर कायम रही।फिर भी मीडिया का फोकस इन पर क्यों रहता है? पहला कारण परिवार का ब्रांड है। नेहरू-गांधी परिवार भारतीय राजनीति का सबसे पुराना राजनीतिक वंश माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा और राजीव गांधी तक, यह नाम ही समाचार बन जाता है। मीडिया हाउस जानते हैं कि राहुल गांधी का कोई बयान चाहे “चौकीदार चोर है” वाला हो या फिर देश को हिंदू आतंकवाद से खतरा बताने वाला तुरंत वायरल हो जाता है। प्रियंका की साड़ी-स्टाइल या भावुक अपील पर टीआरपी बढ़ती है। 2024 चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कई न्यूज चैनलों ने घंटों कवर किया, जबकि बीजेपी के विकसित भारत अभियान को अपेक्षाकृत कम। टीआरपी के आंकड़े बताते हैं कि राहुल के भाषणों पर डिबेट शो की रेटिंग 2-3 पॉइंट तक ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि विवाद बिकता है। राहुल के विदेशी दौरे, अमेरिका और यूके में “भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है” जैसे बयान, अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी प्रमुखता से दिखाता है, जिसे भारतीय चैनल भी तुरंत उठाते हैं।

दूसरा कारण मीडिया का राजनीतिक एजेंडा माना जाता है। मुख्यधारा मीडिया के एक हिस्से में लेफ्ट-लिबरल विचारधारा का प्रभाव अब भी मजबूत बताया जाता है। कुछ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म राहुल-प्रियंका को मोदी के विकल्प के रूप में पेश करते हैं। यही वजह है कि 2023 में मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी के मार्च को कई चैनलों ने लाइव दिखाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के बयान को कम प्राथमिकता मिली। प्रियंका के महिलाओं के लिए न्याय अभियान को फेमिनिस्ट एंगल से हाइलाइट किया गया। कुल मिलाकर यह राहुल-प्रियंका की राजनीति को जिंदा रखने की रणनीति मानी जाती है। अगर कांग्रेस खत्म हो गई, तो विपक्ष के बिना डिबेट शो कैसे चलेंगे? कई न्यूज चैनलों के पैनल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जाता है, भले जनता उन्हें 2014 और 2019 में नकार चुकी हो।2014 में अमेठी में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी की हार, 2019 में रायबरेली में सोनिया गांधी की सीट पर प्रियंका की सक्रियता के बावजूद घटता मार्जिन, और 2024 में राहुल गांधी की वायनाड व रायबरेली दोनों सीटों पर जीत इन सबके बावजूद कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई, जबकि बीजेपी 240 सीटें जीतने में सफल रही।

परीक्षा नहीं, भविष्य लीक हुआ है

-अवनीश कुमार गुप्ता

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएँ अब केवल करियर का माध्यम नहीं रह गई हैं; वे करोड़ों परिवारों की आकांक्षाओं, सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक भविष्य का केंद्र बन चुकी हैं। यही कारण है कि जब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 को कथित पेपर लीक और “क्वेश्चन बैंक” विवाद के बाद रद्द किया गया, तो यह केवल एक परीक्षा का स्थगन नहीं था। यह उस भरोसे पर आघात था, जिसके आधार पर लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं और परिवार अपनी जमा-पूंजी दांव पर लगाते हैं। देशभर से लगभग 24 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। मेडिकल शिक्षा की सीमित सीटों और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के बीच यह परीक्षा देश की सबसे कठिन और निर्णायक परीक्षाओं में मानी जाती है। लेकिन परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से सामने आई रिपोर्टों ने पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार परीक्षा से पहले एक कथित क्वेश्चन बैंक छात्रों तक पहुंचा, जिसमें मौजूद बड़ी संख्या में प्रश्न वास्तविक परीक्षा से मेल खाते पाए गए।

राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह की जांच में सामने आया कि सीकर, जयपुर और झुंझुनूं जैसे कोचिंग केंद्रों में परीक्षा से पहले प्रश्न सामग्री प्रसारित हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह सामग्री व्हाट्सऐप और अन्य एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई छात्रों तक पहुंची। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कथित प्रश्न बैंक में 300 से अधिक प्रश्न थे, जिनमें से लगभग 150 प्रश्न हूबहू परीक्षा में दिखाई दिए। यदि यह तथ्य पूरी तरह सिद्ध होता है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि संगठित परीक्षा अपराध की श्रेणी में आता है। इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पक्ष यह नहीं कि पेपर लीक हुआ या नहीं; बल्कि यह है कि अब छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल मेहनत पर्याप्त नहीं रह गई। यही भावना किसी भी लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है।

भारत में मेडिकल सीटों की स्थिति अत्यंत असंतुलित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में एमबीबीएस की कुल सीटें लगभग 1.20 लाख के आसपास हैं, जबकि परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 24 लाख तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा अर्थ है कि हर 20 छात्रों में केवल 1 छात्र को मेडिकल सीट मिल पाती है। यह अनुपात न केवल प्रतियोगिता को असामान्य रूप से कठोर बनाता है, बल्कि मानसिक दबाव को भी कई गुना बढ़ा देता है। कोटा, सीकर, पटना, दिल्ली और हैदराबाद जैसे कोचिंग केंद्र अब केवल शिक्षा के स्थल नहीं, बल्कि एक समानांतर परीक्षा अर्थव्यवस्था में बदल चुके हैं। एक छात्र की वार्षिक तैयारी लागत औसतन 2 लाख से 5 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। इसमें कोचिंग फीस, हॉस्टल, भोजन, टेस्ट सीरीज, किताबें और डिजिटल सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। लाखों परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में निवेश करते हैं कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष होगी। लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है, तब केवल परीक्षा केंद्र नहीं टूटता – पूरा पारिवारिक संतुलन हिल जाता है।

कई छात्रों ने सोशल मीडिया मंचों पर लिखा कि वे दोबारा उसी मानसिक स्थिति में तैयारी नहीं कर पाएंगे। कुछ ने वर्षों की मेहनत को “अनिश्चित व्यवस्था का शिकार” बताया। यह प्रतिक्रिया केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक थकान का संकेत है जो आज के प्रतियोगी युवा समाज की वास्तविकता बन चुकी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज का युवा केवल परीक्षा नहीं दे रहा, बल्कि वह लगातार तुलना, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव के बीच जी रहा है। एक ओर परिवार की उम्मीदें हैं, दूसरी ओर लगातार बढ़ती फीस, सीमित अवसर और अस्थिर रोजगार बाजार। ऐसे समय में यदि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगें, तो उसका प्रभाव केवल रिजल्ट तक सीमित नहीं रहता; वह युवाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक भरोसे को भी प्रभावित करता है। नीट विवाद कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कभी तकनीकी गड़बड़ी, कभी सर्वर फेल, कभी पेपर लीक और कभी मूल्यांकन विवाद – इन घटनाओं ने परीक्षा एजेंसियों की विश्वसनीयता को कमजोर किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि देश में एक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी रूप से सुरक्षित परीक्षा प्रणाली विकसित हो सके। लेकिन आज वही संस्था लगातार विवादों के केंद्र में दिखाई दे रही है। यह केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि संस्थागत जवाबदेही का प्रश्न है। परीक्षा प्रणाली केवल तकनीक से सुरक्षित नहीं होती। किसी भी परीक्षा की विश्वसनीयता पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई पर आधारित होती है। यदि इन तीनों में कमी आए, तो तकनीकी सुरक्षा भी पर्याप्त नहीं रह जाती।

नीट 2026 विवाद ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल युग में परीक्षा अपराधों का स्वरूप बदल चुका है। पहले प्रश्नपत्र फोटोकॉपी और कागजों के माध्यम से लीक होते थे; अब एन्क्रिप्टेड ऐप, निजी चैनल, क्लाउड शेयरिंग और फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स जैसे डिजिटल संकेत पूरे नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। यानी परीक्षा सुरक्षा अब केवल परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं रह सकती। इस पूरे विवाद की सबसे गहरी परत सामाजिक असमानता से जुड़ी हुई है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं लंबे समय तक सामाजिक गतिशीलता का माध्यम रही हैं। गांवों और छोटे शहरों के लाखों छात्रों के लिए यह अवसर था कि वे सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन की दिशा बदल सकें। लेकिन जब परीक्षा प्रक्रिया पर संदेह बढ़ने लगे, तब यह विश्वास कमजोर होता है कि मेहनत से सफलता संभव है।

एक ओर वे छात्र हैं जो लाइब्रेरी, किराये के कमरों और सीमित संसाधनों के बीच तैयारी करते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे नेटवर्क दिखाई देते हैं जिनके पास तकनीकी पहुंच, प्रभाव और गोपनीय सूचना पहले से उपलब्ध रहती है। यही वह बिंदु है जहां प्रतियोगिता धीरे-धीरे समान अवसर से हटकर “संपर्क आधारित लाभ” में बदलने लगती है। यदि यह धारणा युवाओं के मन में स्थायी रूप से बैठ जाती है, तो उसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास को भी कमजोर करेगा। परीक्षा रद्द होने का आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत गंभीर है। लाखों छात्रों को पुनः यात्रा, आवास, अध्ययन सामग्री और मानसिक तैयारी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिन परिवारों ने पहले ही भारी खर्च किया है, उनके लिए यह दोहरी मार जैसी स्थिति है। यदि औसतन प्रत्येक छात्र की तैयारी और परीक्षा से संबंधित लागत 3 लाख रुपये मानी जाए, तो 24 लाख छात्रों पर यह राशि लगभग 72 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचती है। यह केवल एक अनुमानित गणना है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं आज एक विशाल आर्थिक ढांचे में बदल चुकी हैं।

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, लेकिन यही युवा वर्ग आज सबसे अधिक असुरक्षित और बेचैन दिखाई देता है। रोजगार की सीमित संभावनाएं, बढ़ती प्रतियोगिता, परीक्षा विवाद और आर्थिक दबाव – ये सभी मिलकर एक गहरी सामाजिक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। युवाओं की नाराजगी केवल किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं है; यह उस भावना से जुड़ी है कि व्यवस्था उनकी मेहनत के अनुरूप भरोसेमंद नहीं रह गई। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर केवल विरोध नहीं, बल्कि व्यंग्य, निराशा और अविश्वास का स्वर भी तेज होता जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अत्यंत गंभीर संकेत माना जाता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की स्थिरता केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि उसकी युवा पीढ़ी के भरोसे से तय होती है।

सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी है और पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन प्रश्न केवल दोषियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। आवश्यकता उस व्यापक ढांचे की समीक्षा की है जिसमें देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यह समय केवल तकनीकी सुधारों का नहीं, बल्कि संस्थागत पुनर्विश्वास का है। परीक्षा प्रणाली को इस स्तर तक पारदर्शी बनाना होगा कि छात्रों को यह महसूस हो सके कि उनका भविष्य किसी “नेटवर्क” या “लीक” से नहीं, बल्कि उनकी मेहनत से तय होगा। नीट 2026 विवाद ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल रोजगार या शिक्षा नहीं, बल्कि भरोसे की पुनर्स्थापना है। क्योंकि जब युवाओं का विश्वास टूटता है, तब केवल परीक्षा नहीं हारती – पूरा समाज असुरक्षित महसूस करने लगता है।

लोकलुभावन राजनीति और राज्यों पर बढ़ता ऋण बोझ

-प्रियंका सौरभ

भारत में राज्यों का लगातार बढ़ता ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात आज केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं, बल्कि देश की वित्तीय स्थिरता और सहकारी संघवाद के लिए गंभीर चेतावनी बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश राज्यों का सार्वजनिक ऋण तेजी से बढ़ा है। राजस्व घाटे, लोकलुभावन योजनाओं, कमजोर कर-संग्रह प्रणाली तथा बजट से बाहर लिए गए उधारों ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त आयोगों ने भी समय-समय पर इस बढ़ती ऋण प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में यह संकट राज्यों की विकास क्षमता और संघीय संतुलन दोनों को प्रभावित कर सकता है।

राज्यों के बढ़ते ऋण का सबसे बड़ा कारण लगातार बढ़ता राजस्व घाटा है। कई राज्य अपनी नियमित आय से वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी जैसे खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। परिणामस्वरूप उन्हें सामान्य प्रशासनिक गतिविधियों के लिए भी उधार लेना पड़ता है। यह स्थिति आर्थिक दृष्टि से अत्यंत अस्थिर मानी जाती है क्योंकि उधार का उपयोग उत्पादक निवेश के बजाय दैनिक खर्चों में होने लगता है। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ब्याज भुगतान और पेंशन व्यय लगातार बढ़ रहा है, जिससे विकासात्मक परियोजनाओं के लिए संसाधन सीमित होते जा रहे हैं।

लोकलुभावन राजनीति ने भी इस वित्तीय संकट को गहरा किया है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के दौर में मुफ्त बिजली, कृषि ऋण माफी, मुफ्त परिवहन, नकद सहायता और विभिन्न प्रकार की सब्सिडी योजनाओं का विस्तार हुआ है। यद्यपि सामाजिक कल्याण योजनाएँ लोकतांत्रिक शासन का आवश्यक हिस्सा हैं, लेकिन जब वे वित्तीय क्षमता से अधिक बढ़ जाती हैं, तब वे राजकोषीय अनुशासन को कमजोर कर देती हैं। अधिकांश मुफ्त योजनाएँ दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादकता नहीं बढ़ातीं, जिससे भविष्य में राजस्व सृजन की क्षमता कम हो जाती है और ऋण का बोझ बढ़ता जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता भी सीमित हुई है। पहले राज्यों के पास मूल्य वर्धित कर और अन्य अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से स्वतंत्र राजस्व स्रोत उपलब्ध थे, लेकिन अब वे काफी हद तक केंद्र के हस्तांतरण और वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति पर निर्भर हो गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति में देरी ने राज्यों की वित्तीय समस्याओं को और गंभीर बना दिया। इससे केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय मतभेद बढ़े, जिसने सहकारी संघवाद की भावना को प्रभावित किया।

कमजोर कर आधार भी राज्यों की आर्थिक कमजोरी का एक महत्वपूर्ण कारण है। कई राज्यों में संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और स्थानीय निकाय कर प्रभावी ढंग से वसूले नहीं जाते। नगरपालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण राज्यों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। डिजिटल कर प्रशासन और आँकड़ा-आधारित निगरानी के अभाव में कर चोरी और राजस्व हानि की समस्या बनी रहती है।

इसके अलावा, बजट से बाहर लिए गए उधार और छिपी हुई देनदारियाँ राज्यों की वास्तविक वित्तीय स्थिति को और जटिल बना देती हैं। कई राज्य सार्वजनिक उपक्रमों, बिजली वितरण कंपनियों और विशेष प्रयोजन संस्थाओं के माध्यम से ऋण लेते हैं, जो आधिकारिक बजट में पूरी तरह दिखाई नहीं देते। इससे वास्तविक ऋण स्थिति का सही आकलन कठिन हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बार चेतावनी दी है कि इस प्रकार की छिपी हुई देनदारियाँ भविष्य में बड़े वित्तीय संकट का कारण बन सकती हैं।

पूंजीगत व्यय की कम उत्पादकता भी ऋण वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। यदि उधार लेकर शुरू की गई परियोजनाएँ समय पर पूरी नहीं होतीं या उनसे अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता, तो वे विकास के बजाय वित्तीय बोझ बन जाती हैं। कई राज्यों में प्रशासनिक देरी, भ्रष्टाचार और कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण निवेश का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

राज्यों की बढ़ती ऋण निर्भरता भारतीय संघवाद को भी प्रभावित कर रही है। जब राज्य वित्तीय रूप से कमजोर होते हैं, तो वे अधिक केंद्रीय सहायता, विशेष पैकेज और अतिरिक्त उधारी सीमा की मांग करते हैं। इससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता कम होती है और केंद्र पर निर्भरता बढ़ती है। दूसरी ओर, केंद्र द्वारा उधारी सीमा और वित्तीय शर्तें तय किए जाने से राजनीतिक विवाद उत्पन्न होते हैं। वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति और केंद्रीय कर हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते मतभेद इसी तनाव का उदाहरण हैं।

क्षेत्रीय असमानताएँ भी इस संकट के कारण बढ़ रही हैं। आर्थिक रूप से मजबूत राज्य अपेक्षाकृत बेहतर संसाधन जुटा लेते हैं, जबकि कमजोर राज्य लगातार ऋण जाल में फँसते जाते हैं। इससे विकास का संतुलन बिगड़ता है और संघीय ढाँचे में असमानता की भावना मजबूत होती है।

इस बढ़ते ऋण संकट से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय अनुशासन अपनाना होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों का गंभीरता से पालन आवश्यक है। उधार का उपयोग मुख्यतः पूंजीगत व्यय और उत्पादक निवेश के लिए होना चाहिए, न कि दैनिक खर्चों के लिए। राज्यों को अपने कर आधार को मजबूत करना होगा। वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन बढ़ाने, संपत्ति कर सुधार लागू करने तथा डिजिटल कर प्रशासन को बढ़ावा देने से राज्यों की स्वयं की आय में वृद्धि हो सकती है।

गैर-जरूरी सब्सिडी और लोकलुभावन योजनाओं का युक्तिकरण भी आवश्यक है। सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढाँचे और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, बजट से बाहर लिए गए उधार और सरकारी गारंटी को पूरी पारदर्शिता के साथ बजट में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो सके।

घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली वितरण कंपनियों में संरचनात्मक सुधार भी समय की आवश्यकता है। स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाकर राज्यों का बोझ कम किया जा सकता है। नगरपालिकाओं और पंचायतों को अधिक वित्तीय अधिकार और संसाधन मिलने से विकेंद्रीकरण को भी मजबूती मिलेगी।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राज्यों की आर्थिक मजबूती राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। इसलिए वित्तीय अनुशासन और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। केवल उधार लेकर मुफ्त योजनाएँ चलाना दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाकर पारदर्शी, उत्तरदायी और टिकाऊ वित्तीय व्यवस्था विकसित करनी होगी। अंततः, राज्यों का बढ़ता ऋण संकट भारतीय अर्थव्यवस्था और सहकारी संघवाद दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि समय रहते संरचनात्मक सुधार नहीं किए गए, तो भविष्य में विकास व्यय, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। वास्तविक समाधान कठोर मितव्ययिता में नहीं, बल्कि स्मार्ट वित्तीय प्रबंधन में निहित है, जहाँ उधार का उपयोग उत्पादक निवेश के लिए हो, कर आधार मजबूत हो और सार्वजनिक व्यय अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बने।

पीएम मोदी की सोना खरीदने से परहेज की अपील पर भिवंडी के सराफा कारोबारियों में नाराजगी

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से एक वर्ष तक सोना खरीदने से परहेज करने और मितव्ययिता अपनाने की अपील के बाद भिवंडी के सराफा व्यवसायियों और सुवर्ण कारीगरों में नाराजगी देखी जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि इस फैसले का असर छोटे-बड़े ज्वेलर्स, कारीगरों और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।भिवंडी सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा राज्य संगठन के उपाध्यक्ष प्रदीप (पप्पू) राका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नागरिक भविष्य की बचत और निवेश के उद्देश्य से सोने में निवेश करते हैं। ऐसे में यदि लंबे समय तक सोने की खरीद बंद होती है तो इसका सीधा असर सराफ बाजार, शेयर बाजार और लाखों कारोबारियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले नागरिकों को इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए, ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति न बने। वर्तमान में विवाह समारोहों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोगों को नया सोना खरीदने के बजाय पुराने सोने का पुनर्चक्रण कर उसका उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है। इससे सोने के आयात में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कारोबारियों को भी नुकसान नहीं होगा। सराफ कारोबारियों का मानना है कि यदि सोना खरीद पर लंबे समय तक रोक जैसी स्थिति बनती है तो छोटे दुकानदारों और कारीगरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।

नीट - यूजी की परीक्षा रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण

मुंबई (उत्तरशक्ति)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिकारिक तौर पर नीट - यूजी परीक्षा रद्द कर दी, जिसे देशभर के कॉलेजों में मेडिकल दाखिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ऐतिहासिक फैसला 3 मई को आयोजित परीक्षा में व्यापक अनियमितताओं के प्रारंभिक जांच के बाद लिया गया। अब इस मामले की गहन जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों ने नीट - यूजी परीक्षा को रद्द किए जाने पर तीव्र आक्रोश प्रकट किया है। अनेक छात्रों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि हमने बड़े ही मेहनत के साथ नीट की तैयारी की थी लेकिन परीक्षा रद्द होने से हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई। हमारे सपनों पर पानी फिर गया। वहीं राकांपा मुम्बई प्रदेश के उपाध्यक्ष संजीव उपाध्याय ने नीट- यूजी की परीक्षा रद्द किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नीट - यूजी की परीक्षा केंद्र सरकार के अधीन होती है। इस परीक्षा में पूरे देश के कई लाख छात्र शामिल होते हैं। इस परीक्षा के रद्द किए जाने से बड़ी संख्या में छात्रों के सपनों पर पानी फिर गया है। उन्होंने आगे कहा कि कितनी मेहनत और लगन के साथ नीट - यूजी परीक्षा की तैयारी छात्रों द्वारा की गई थी। लेकिन अंतिम समय में परीक्षा रद्द किए जाने से छात्रों और अभिभावकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

भवन निर्माता राजेश व सुरेश सिंह की मां की तेरहवीं में शामिल हुए 4000 से अधिक लोग

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। माँ का महत्व निःस्वार्थ प्रेम, सुरक्षा, और संस्कार की नींव के रूप में सर्वोच्च है। वह बच्चे की पहली शिक्षक, मार्गदर्शक और सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो निस्वार्थ भाव से पालन-पोषण करती हैं। उनके बिना परिवार अधूरा है, और उनका आशीर्वाद जीवन भर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। मीरा भायंदर के प्रख्यात भवन निमार्ता राज रीयल्टी ग्रुप के डायरेक्टर राजेश सिंह एवं सुरेश सिंह की मां धानफूल फुलराज सिंह का 25 अप्रैल को मुंबई में निधन होने के बाद उनके पैतृक गांव भरसथ, गोपालापुर, जौनपुर स्थित सिंह हाउस में 7 मई को तेरहवीं का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4000 से अधिक लोग शामिल हुए । अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की धानफूल देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों के अलावा मीरा भायंदर, ठाणे , वसई, मुंबई, कल्याण से आये सैकड़ो लोगों ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी राज्य मंत्री अमरीश सिंह भोला, विधायक आरके पटेल, पूर्व विधायक लीना तिवारी, पूर्व विधायक सुषमा पटेल, पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, भाजपा नेता मनोज सिंह, अपना दल जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, राहुल सिंह, अरविंद सिंह, सोनू सिंह सुमित दास वर्तमान ब्लाक प्रमुख , अनेक पूर्व ब्लाक प्रमुख, भाजपा जिला महामंत्री स्कंद पटेल, भवन निमार्ता पंकज सिंह, आभार व्यक्त किया।

साल का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट डेब्यू - रोहित शर्मा सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया पर

मुंबई/ पटना। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया देशभर के दर्शकों के लिए वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा को लेकर आ रहा है। उनके बहुप्रतीक्षित एंटरटेनमेंट डेब्यू की झलक देते हुए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने एक रोमांचक टीजर लॉन्च किया है, जिसने फैन्स के बीच उत्सुकता और चर्चा का माहौल बना दिया है। टीजर में दिखाया गया है कि फैन्स रोहित के चारों ओर उमड़ पड़े हैं और उनसे उनकी मशहूर लाइन कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा दोहराने की गुजारिश कर रहे हैं। यह मजेदार अंदाज उस पल को याद दिलाता है जब मैदान पर कही गई एक सहज टिप्पणी पॉप-कल्चर का वायरल मोमेंट बन गई थी। टीजर में इस डायलॉग के इर्द-गिर्द बनी दीवानगी को ह्यूमर के साथ दिखाया गया है। इस जबरदस्त क्रेज पर रोहित हंसते हुए कहते हैं, दो लाइन क्या बोल दी, इतना वायरल हो गया जब मेरा पूरा शो आएगा तो क्या होगा? ह्यूमर, करिश्मा और रहस्य से भरपूर यह हल्का-फुल्का टीजर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की ओर से साल के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट डेब्यू की नींव रखता है।

केडीएमसी में मनसे कार्यालय के उद्घाटन में शिंदे शिवसेना के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

कल्याण (उत्तरशक्ति)। डोंबिवली महानगर पालिका में मनसे कार्यालय के उद्घाटन में शिंदे शिवसेना के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। बतादें की कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नए पक्ष कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब मुख्यमंत्री Eknath Shinde गुट की शिवसेना के कई बड़े नेता कार्यक्रम में नजर आए। इस मौके पर दोनों दलों के नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को जन्म दे दिया है। स्थानीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मनसे पदाधिकारियों के साथ-साथ शिंदे शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से इसे सामान्य राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है और आने वाले समय में कौन-सा नया गठबंधन सामने आ सकता है।

आम जनता के लिए यह पूरा घटनाक्रम समझना आसान नहीं है। एक ओर नेता अलग-अलग विचारधाराओं की बात करते हैं, तो दूसरी ओर मंच साझा करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में मतदाता असमंजस में हैं कि आखिर राजनीतिक समीकरणों का असली अर्थ क्या है।

फिलहाल, कल्याण-डोंबिवली का यह उद्घाटन समारोह केवल एक कार्यालय उद्घाटन न रहकर राज्य की राजनीति में नई चर्चा का केंद्र बन गया है।

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटील का हाल-चाल जानने पुणे पहुंचे कृपाशंकर सिंह

मुंबई (उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह अपने संबंधों के निर्वाह को लेकर हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटील को अपना राजनीतिक गुरु और मां का दर्जा देने वाले कृपाशंकर सिंह आज उनका हाल-चाल जानने के लिए अचानक पुणे स्थित उनके आवास पर पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक उनके साथ समय बिताया। उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। श्रीमती पाटिल ने कृपाशंकर को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। इस बारे में पूछे जाने पर कृपाशंकर ने कहा कि श्रीमती प्रतिभाताई पाटील न सिर्फ उनकी राजनीतिक गुरु हैं, अपितु वह उन्हें अपनी मां के समान आदर करते हैं। उनका स्नेह और आशीर्वाद उन्हें निरंतर मिलता रहता है। कृपाशंकर ने कहा कि मैंने उनसे मिलकर न सिर्फ उनका हाल-चाल जाना अपितु ईश्वर से उनके स्वस्थ जीवन की प्रार्थना भी की।

कल्याण में मामा ने की भांजे की हत्या - आरोपी मामा गिरफ्तार

मृतक का फोटो

कल्याण (उत्तरशक्ति)। मोबाइल पर लूडो गेम खेलने को लेकर हुए विवाद में मामा ने अपने ही भांजे की गला रेतकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज घटना मंगलवार रात को कल्याण में सामने आई। हत्या करने वाला मामा नाबालिग बताया जा रहा है, जिसे खड़कपाड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, कल्याण पश्चिम के उंबर्डे-कोळीवली परिसर स्थित रॉयल ढाबे पर मामा-भांजा दोनों काम करते थे। मंगलवार रात मोबाइल पर लूडो गेम खेलने को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर नाबालिग मामा ने अपने भांजे गोखील भीम बहादूर पर चाकू से गले पर हमला कर दिया।

चाकू के कई वार होने से गोखील का गला गंभीर रूप से कट गया। अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही खड़कपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। भांजे की हत्या के मामले में नाबालिग मामा को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है।

सांसद ने कल्याण-डोंबिवली में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने का लिया बड़ा फैसला

कल्याण (उत्तरशक्ति)। बुधवार को KDMC मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में Shrikant Shinde ने कल्याण के रुक्मिणीबाई अस्पताल और डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन दोनों अस्पतालों का पुनर्विकास Thane Civil Hospital की तर्ज पर किया जाए, जहां 500 बेड की मल्टीस्पेशालिटी सुविधा और मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि डोंबिवली में निमार्णाधीन कैंसर अस्पताल का काम तेजी से चल रहा है और अगले वर्ष से यह नागरिकों की सेवा में उपलब्ध होगा।

इस बैठक में KDMC आयुक्त अभिनव गोयल, महापौर हर्षाली चौधरी, स्थायी समिति सभापति मल्लेश शेट्टी सहित महापालिका के वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर के विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में Shrikant Shinde ने कहा कि कल्याण ग्रामीण के 27 गांवों की पानी की समस्या अगले छह महीनों में अमृत योजना के तहत स्थायी रूप से हल कर दी जाएगी। परियोजना के बढ़े हुए बजट और लंबित जल कनेक्शन कार्यों के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, जिसे Eknath Shinde ने मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि KDMC भी 50 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जिससे इस परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इस राशि से जल पाइपलाइन कनेक्टिविटी, पानी की टंकियों की जोड़ाई और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

शहर की पुरानी जल पाइपलाइनों को बदलने के लिए KDMC ने 268 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटाने की अनुमति मिलने के बाद KDMC भी इस विकल्प पर विचार कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है।शहर की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए रिंग रोड परियोजना की भी समीक्षा की गई।

सारनाथ में राष्ट्रीय चौहान महासंघ की त्रैवार्षिक सभा व सम्मान समारोह सम्पन्न, नई कार्यकारिणी की गयी घोषित

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। राष्ट्रीय चौहान महासंघ की त्रैवार्षिक सर्वसाधारण सभा एवं सम्मान समारोह 10 मई 2026 को संस्था के छात्रावास एवं अतिथिगृह, सारनाथ (वाराणसी) में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभा में नई राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। रामसिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष, गोविन्द चौहान को राष्ट्रीय महासचिव तथा रमेश चौहान को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं डॉ. संतोष कुमार चौहान को उत्तर प्रदेश, हरिश्चंद्र चौहान को महाराष्ट्र, शिवानन्द चौहान को बिहार, लल्लन चौहान को गुजरात तथा कन्हैयालाल चौहान को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रामउजागर चौहान ने की, जबकि संस्थापक अध्यक्ष मुनीब सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर नरेन्द्रकुमार चौहान ने कहा कि संगठन में चुनाव के कारण गुटबाजी बढ़ती है और इससे संगठन कमजोर होता है। इस बार सभी पदों पर एक-एक नाम आने से चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ, जो संगठन की एकता का प्रतीक है। उन्होंने नई कार्यकारिणी को आगामी तीन वर्षों के लिए शुभकामनाएं दीं।

भूमि वर्ल्ड के अवैध निर्माण पर यदि दो दिनों में कार्यवाही नहीं हुई तो 15 दिन में होगा उग्र आंदोलन : सांसद सुरेश म्हात्रे

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। मुंबई-नाशिक महामार्ग स्थित पिंपळास गांव की सीमा में बने भूमि वर्ल्ड गोदाम संकुल के कथित अवैध निर्माण को लेकर सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद एमएमआरडीए और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण का संदेह पैदा हो रहा है।

बुधवार को आयोजित पत्रकार परिषद में सांसद सुरेश म्हात्रे ने कहा कि यदि प्रशासन ने अगले दो दिनों में कार्रवाई नहीं की तो स्थानीय किसानों के साथ मिलकर आगामी 15 दिनों के भीतर निर्माण स्थल पर तीव्र आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि उस दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सांसद ने आरोप लगाया कि भूमि वर्ल्ड के विकासक प्रकाश पटेल द्वारा लगभग एक करोड़ वर्गफुट निर्माण किया गया है, जिसमें सरकार की 25 एकड़ गुरुचरण भूमि तथा किसानों की जमीन भी शामिल है। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर करीब साढ़े पांच लाख वर्गफुट का मॉल भी बनाया गया है, जिसे उन्होंने पूरी तरह अवैध बताया। उन्होंने दावा किया कि इस निर्माण के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। एमएमआरडीए ने सूचना के अधिकार के तहत उन्हें लिखित रूप में इसकी जानकारी दी है। सुरेश म्हात्रे ने कहा कि वर्ष 2018, 2019 और 2021 में मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि कोई नया निर्माण न किया जाए तथा अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद प्रशासन मौन धारण किए हुए है, जो न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा निर्माण प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। सांसद ने बताया कि वे अंतिम बार ई-मेल के माध्यम से एमएमआरडीए और ठाणे जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए निवेदन करेंगे। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सांसद ने यह भी मांग की कि कथित रूप से विकासक को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की जाए।

मुंबई कॉमिक कॉन 2026 में वीकेंड पर 55,000 से ज्यादा फैंस की मौजूदगी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ

मुंबई। मुंबई का सबसे बड़ा फैनडम और पॉप कल्चर उत्सव मुंबई कॉमिक कॉन 2026 बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 55,000 से अधिक लोगों शामिल हुए। यह कार्यक्रम 9 और 10 मई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया।

मारुति सुजुकी अरेना द्वारा प्रस्तुत और क्रंचीरोल के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग और MAITRI (महाराष्ट्र इंडस्ट्री, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल) का भी इसमें सहयोग रहा। इस कार्यक्रम ने ऊर्जा और उत्साह से भरा एक शानदार वीकेंड प्रस्तुत किया। इसमें शहर की जबरदस्त फैनडम कल्चर का जश्न मनाया गया और यह फिर से साबित हुआ कि मुंबई भारत में पॉप कल्चर और फैनडम का एक प्रमुख केंद्र है।

दोनों दिनों में फैंस बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। देशभर से हजारों लोग दो दिन के कॉमिक्स, एनीमे, गेमिंग, कॉसप्ले, कलेक्टिबल्स और इमर्सिव अनुभवों का आनंद लेने आए थे। कुछ फैंस खास तौर पर देश के अलग-अलग हिस्सों से फ्लाइट लेकर पहुंचे, जबकि स्थानीय लोग सुपरहीरो की वेशभूषा में कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरा आयोजन स्थल उत्साह से भरा हुआ था और अलग-अलग गतिविधियों के कारण वहां त्योहार जैसा माहौल बन गया था। फैंस का जोश और सेलिब्रेशन देखकर एक बार फिर साबित हुआ कि मुंबई कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं करती। नोडविन गेमिंग के सह-संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षत राठी ने कहा, मुंबई की फैन संस्कृति बहुत खास है क्योंकि यहां लोग सच में साथ मिलकर अनुभव करना पसंद करते हैं। चाहे कॉन्सर्ट हो, क्रिकेट हो, त्योहार हों या लाइव इवेंट्स, लोग बहुत उत्साह से शामिल होते हैं और कॉमिक कॉन में भी यही देखने को मिला। इस वीकेंड की खास बात यह रही कि मुंबई ने कॉमिक कॉन को अपनी सामाजिक संस्कृति का हिस्सा बना लिया।

टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी में अब मिलेगा ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

मुंबई। भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवी) ने आज अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी में एएमटी (ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) की शुरूआत की घोषणा की। इसके साथ अल्ट्रोज आईसीएनजी अब भारत की पहली और एकमात्र प्रीमियम हैचबैक बन गई है, जो सीएनजी पावरट्रेन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प देती है। नई अल्ट्रोज आईसीएनजी एएमटी की शुरूआती कीमत 8.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह लॉन्च कंपनी के 'फील स्पेशल' ब्रांड प्रपोज़िशन को और मजबूत करता है, जिसमें सीएनजी की बेहतर माइलेज और ऑटोमैटिक ड्राइविंग की सुविधा एक साथ मिलती है, साथ ही इस सेगमेंट में सबसे व्यापक मल्टी-पावरट्रेन लाइन-अप की पेशकश भी जारी रखता है।

टाटा अल्ट्रोज के नए आईसीएनजी एएमटी मॉडल को अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से कई वैरिएंट्स में पेश किया गया है। इसके शुरूआती वैरिएंट 'प्योर' की एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत 8,69,990 रुपये रखी गई है, जबकि 'प्योर एस' वैरिएंट 8,99,990 रुपये में उपलब्ध है। मध्यम श्रेणी में 'क्रिएटिव' वैरिएंट की कीमत 9,56,990 रुपये और 'क्रिएटिव एस' की कीमत 9,81,990 रुपये तय की गई है। इसके सबसे प्रीमियम और टॉप-स्पेक वैरिएंट 'अकम्प्लीश्ड' की कीमत 10,76,990 रुपये है। ये सभी कीमतें दिल्ली के एक्स-शोरूम दरों के अनुसार हैं। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर श्री विवेक श्रीवत्स ने लॉन्च पर कहा, टाटा अल्ट्रोज ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में डिजाइन, सुरक्षा और पावरट्रेन विकल्पों के मामले में लगातार नए मानक स्थापित किए हैं। भारत में सीएनजी एक तेजी से बढ़ता हुआ ईंधन विकल्प बन गया है, जिसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 25 में 19% और वित्त वर्ष 26 में 22% तक पहुंच चुकी है, और यह वृद्धि अब सिर्फ पारंपरिक बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि नए क्षेत्र भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अल्ट्रोज आईसीएनजी में एएमटी जोड़ने का उद्देश्य सीएनजी वाहनों में बढ़ती सुविधा की जरूरत को पूरा करना है। यह अपडेट अल्ट्रोज को अपने सेगमेंट में सबसे बहुआयामी और प्रीमियम पेशकश बनाता है, जो माइलेज, ड्राइविंग आराम और रोजमर्रा की उपयोगिता का सही संतुलन देती है, बिना स्पेस या सुरक्षा से समझौता किए। अल्ट्रोज आईसीएनजी एएमटी के बारे में: टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी में 1.2 लीटर रेवोट्रॉन आईसीएनजी इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 73.5 पीएस पावर और 103 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इसमें पहली बार एएमटी ट्रांसमिशन जोड़ा गया है, जिससे ड्राइविंग और भी आसान और आरामदायक हो जाती है, खासकर शहर के ट्रैफिक में। इसकी आईसीएनजी तकनीक में एक एडवांस्ड सिंगल ईसीयू सिस्टम है, जो पेट्रोल और सीएनजी मोड के बीच स्मूद और बिना झटके के स्विच करने में मदद करता है। इसके अलावा सेगमेंट में पहली बार सीएनजी मोड में डायरेक्ट स्टार्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे सुविधा और बढ़ जाती है और ढलानों पर तथा लंबी दूरी की यात्रा में भी लगातार बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। कंपनी की ट्विन-सिलेंडर आईसीएनजी तकनीक में सिलेंडर को बूट स्पेस के नीचे इस तरह फिट किया गया है कि सामान रखने की जगह पर कोई खास असर नहीं पड़ता।

नीम करौली बाबा

उत्तरशक्ति

* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति

* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा

*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पत्राचार कार्यालय :

उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)

मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37

मो.- 9554493941

email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामी: शरद फागुराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।

पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

बारातियों से भरी अनियंत्रित पिकअप खेत में पलटी, दूल्हे के चचेरे भाई सहित तीन की मौत

हादसे में 12 लोग घायल

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। जिले के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के कठार गांव के पास मंगलवार की रात करीब 10 बजे बड़ा हादसा हो गया। बारातियों से भरा पिकअप तेज घुमावदार मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई अजय व विनोद गोंड के अलावा राजन गोंड की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। चतरा पीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद 11 गंभीर रूप से घायलों को पांच एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लोढ़ी रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की। हादसे सूचना पर डीएम चर्चित गौड़ और एसपी अभिषेक वर्मा भी मौके पर पहुंच गए।

रामपुर बरकोनिया एसओ की विनोद यादव ने बताया कि मिजार्पुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के चुनरी बांध पुरवा निवासी शिवकुमार के बेटे अजय गोंड की शादी रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के चेनरी टोला निवासी विक्रम की बेटी से तय थी। मंगलवार की रात करीब 10 बजे बरात चेनरी टोला आ रही थी। कठार गांव के पास तेज घुमावदार मोड़ पर बरातियों से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। पिकअप में सवार बरातियों को बाहर निकालकर चतरा पीएचसी पहुंचाया गया। घायलों में आशीष, गोलू, रामाशीष, श्याम सुंदर, रामजनम, आकाश, रामसुंदर, बिहारी, रोहित सहित 15 लोग हैं। इनमें से गंभीर रूप से 11 घायलों को पांच एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां पर डॉक्टरों ने अजय गोंड, विनोद गोंड और राजन गोंड की मौत की पुष्टि की। घटना की सूचना परिजनों को दी गई है। घायल दिनेश और भोंदू को वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के चनरी बांध गांव में दो दिनों में भाई और बहन दोनों की शादी होनी थी। मंगलवार को भाई की बारात गई तो बुधवार को बहन की बरात घर पर आनी थी। मंगलवार को शादी कर भाई दुल्हन लेकर आता और बहन के दूल्हे का स्वागत करता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार की रात में मातम का शोर घर पर पहुंच गया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के चनरी बांध गांव से शिवकुमार गोंड के पुत्र अजय गोंड की बारात सोनभद्र गई थी। अजय तीन भाई और तीन बहन है। बुधवार को अजय की छोटी बहन संजू की भी शादी होनी थी। इससे पहले भाई की बरात से लौटते समय पिकअप हादसे का शिकार हो गई। जिसमें तीन लोगों की जान चली गई।

51 लाख के वेतन घोटाले में जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार

मो.इमरान फारूख

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। समाज कल्याण विभाग में सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन पर शासन द्वारा वेतन भुगतान पर रोक लगाए जाने के बावजूद 10 अवैध शिक्षकों को वेतन जारी करने का आरोप है।

बताया जा रहा है कि डीडी समाज कल्याण आर.के. चौरसिया की ओर से नगर कोतवाली में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और पटल सहायक कसेन्द्र बहादुर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि दोनों अधिकारियों ने शासनादेश की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को वेतन जारी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया।

मामले की जांच मंडलायुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा गठित समिति ने की। जांच में सामने आया कि शासन की रोक के बावजूद 10 शिक्षकों को करीब 51.46 लाख रुपये का वेतन भुगतान किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की संस्तुति की गई थी।

बुधवार को पुलिस ने राजेश चौधरी को कुंवर सिंह उद्यान के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

विश्व मातृदिवस पर डॉ.पूर्णिमा पाण्डेय पूर्णा को मिला साहित्य रत्न सम्मान

साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज द्वारा साहित्यकार सत्कार: आपके द्वार योजना में हुआ अभिनंदन

प्रयागराज (उत्तरशक्ति)। मौलिक विचार एवं साहित्यिक सर्जना की प्रतिनिधि पत्रिका साहित्यांजलि प्रभा द्वारा प्रवर्तित

लोकप्रिय प्रकाशन संस्थान साहित्यांजलि प्रकाशन की ओर से प्रत्येक माह में दिया जाने वाला साहित्य रत्न सम्मान इस माह प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. पूर्णिमा पाण्डेय पूर्णा को दिया गया। प्रीतम नगर स्थित डॉ. पूर्णिमा पाण्डेय पूर्णा के आवास पर वरिष्ठ साहित्यकार विजयलक्ष्मी विभा की अध्यक्षता एवं ख्यातिलब्ध साहित्यकार डॉ. उषा मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। अतिविशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ जया मोहन एवं अतिथि साहित्यकार रचना सक्सेना मंच पर विराजमान रहीं। स्वागत वंदना डॉ योगेंद्र कुमार मिश्र विश्वबंधु तथा डॉ राम लखन चौरसिया वागीश द्वारा किया गया। पंडित राकेश मालवीय मुस्कान ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। डॉ.राम सुख यादव, शम्भूनाथ श्रीवास्तव शंभु, रंजन पाण्डेय, श्याम फतनपुरी, राकेश कुमार पाण्डेय, अश्विन पाण्डेय, सुधीर कुमार तिवारी, जयश्री शुक्ला, पूनम पांडेय एवं अन्य कई वरिष्ठ रचनाकारों की गरिमा पूर्ण उपस्थिति में डॉ. भगवान प्रसाद उपाध्याय के संचालन में डॉ पूर्णिमा पाण्डेय पूर्णा को साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज द्वारा साहित्य रत्न सम्मान-पत्र, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र, मोतीमाल व साहित्य प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंच संचालक डॉ. भगवान प्रसाद उपाध्याय को भी शाल ओढ़ाकर राकेश कुमार पाण्डेय ने सम्मानित किया। उपस्थित कवियों ने मातृदिवस पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत किया। साहित्यांजलि प्रभा के सह-सपादक जाने माने कवि कलाकार रवीन्द्र कुशवाहा ने यह खबर मीडिया को दी।सम्मानित साहित्यकार डॉ.पूर्णिमा पाण्डेय पूर्णा ने कहा कि यह क्षण मेरे लिए अत्यंत गौरव पूर्ण है। सभी मंचासीन अतिथियों ने पूर्णिमा पाण्डेय जी को अपनी शुभकामनाएं दीं।

निराश्रित पशुओं के भरण पोषण हेतु दान में मिले भूसा लदे वाहनों को अपर निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

निराश्रित पशुओं हेतु अब तक 600 कुंतल से अधिक भूसा एकत्र, दानदाताओं ने बढ़ाया सहयोग

वाराणसी (उत्तरशक्ति) जनपद के रोहनिया में, प्रदेश सरकार के निदेर्शानुसार निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण के लिए भूसा और भूसा क्रय हेतु धनराशि संकलित करने हेतु

चलाए जा रहे अभियान के तहत खुशीपुर बाईपास स्थित एचआरएस भूसा भंडार के पास हाईवे पर बुधवार को पशुपालन विभाग वाराणसी मंडल के अपर निदेशक ग्रेड 2 डॉक्टर आर बी राम तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार सिंह ने दान राशि से क्रय 300 क्विंटल भूसा लदे सात वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ठठरा, बंदेपुर, परसरा, नदोय, खरावन आदि विभिन्न गौशालयों के लिए रवाना किया।उक्त अधिकारियों ने कहाकि गौ सेवा से भगवान की पूजा के बराबर फल मिलता है। उन्होंने कहा कि वाराणसी जनपद के सभी पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रयासों से जनपद में अब तक 600 क्विंटल से अधिक भूसा एकत्र किया जा चुका है।अधिकारियों ने चोलापुर गौशाला में 90 क्विंटल भूसा दान करने वाले खुशीपुर स्थित एचआर एस भूसा मंडी के संचालक रणदीप सिंह का काफी सराहना किया और सभी दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आम जनता से निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण के लिए अधिक से अधिक सहयोग देने की अपील की।

निराश्रित पशुओं के चारा हेतु इच्छुक व्यक्ति पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग अथवा संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर भूसा अथवा धनराशि दान कर सकते हैं।दानराशि एकत्रित करने में वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी सलारपुर देवेंद्र कुमार सिंह ने 2,11,527 तथा वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी हाथी बाजार ओमप्रकाश सिंह ने ?63,500 की धनराशि संकलित कर उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर पशुधन प्रसार अधिकारी ड़ा वेद प्रकाश सिंह,संघ के महामंत्री शैलेश चौधरी, उमाशंकर मौर्य, दिनेश यादव, ऋषिकांत यादव, हरविंदर सिंह, संजय कुमार, संतोष कुमार, अजय कुमार सिंह, रामू प्रसाद, संजय सिंह, प्रदीप, प्रियांशु इत्यादि अधिकारी व पशु मित्र उपस्थित रहे।

अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ की मौत

कौशाम्बी (उत्तरशक्ति)। चरवा थाना क्षेत्र के मलाक नागर गांव में बुधवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। मूरतगंज से काजू जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात चार पहिया वाहन ने पैदल जा रहे अधेड़ को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मलाक नागर निवासी भगवान दीन पाल पुत्र स्वर्गीय रामसरन खेत की ओर से पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

नौपेड़वा के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बक्सा विकास खंड क्षेत्र के नौपेडवा बाजार के समीप लखनऊ-जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-731) पर बुधवार तड़के भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से एक वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से जा भिड़ा। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो

गया, जबकि चालक बाल-बाल बच गया। जानकारी के अनुसार, जगदीशपुर की ओर से आ रहे वाहन चालक इंद्रजीत सिंह रात करीब 3:30 बजे नौपेडवा बाजार के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही पिकअप ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गया। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक कुछ देर के लिए रुका और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन बाद में वह ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। हादसे के चलते कुछ समय तक राजमार्ग पर अफरा-तफरी और जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

रिश्वत मांगने के आरोप में अतरौलिया थाने के उपनिरीक्षक निलंबित

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अतरौलिया में तैनात उपनिरीक्षक मायापति पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

पुलिस विभाग से जारी जानकारी के अनुसार उपनिरीक्षक पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता बरतने के साथ-साथ रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोप है कि उनके आचरण से आमजन में पुलिस विभाग की नकारात्मक छवि बनी।

बताया गया कि 12 मई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण और समीक्षा के दौरान प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उपनिरीक्षक के निलंबन की कार्रवाई की गई। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि जनपद में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की चेतावनी दी।

स्वस्थ होकर वाराणसी लौटे अजय राय, कार्यकर्ताओं ने पिंडरा में किया स्वागत

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के लखनऊ से स्वस्थ होकर काशी लौटने पर मंगलवार को पिंडरा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और नारों के बीच पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने 'कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद' और

'लड़ेंगे-जीतेंगे' के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर अजय राय ने कहा कि काशी उनकी भूमि, आत्मा और परिवार है। उन्होंने कहा कि बीमारी के दौरान काशीवासियों और कांग्रेस कार्यकताओं की प्रार्थनाओं व शुभकामनाओं से उन्हें नई शक्ति मिली। बाबा विश्वनाथ की कृपा और जनता के आशीर्वाद से वह पुनः जनता के बीच लौटे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी तथा जनहित के सवालों पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे, श्रीप्रकाश सिंह, रामस्नेही पाण्डेय, फसाहत हुसैन बाबू, राजू राम, अशोक सिंह और गिरीश पाण्डेय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने अजय राय के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पर खुशी जताई।

अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी को मिलेगा वैश्विक आर्थिक विस्तार: अरशद खान

जौनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जौनपुर सदर मोहम्मद अरशद खान ने कहा है कि यदि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, तो प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और औद्योगिक पहचान मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

पीडीए भवन कटघरा, जौनपुर से जारी अंतरराष्ट्रीय प्रेस विज्ञप्ति में अरशद खान ने कहा कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति, वैश्विक निवेश और व्यापारिक साझेदारियों को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को वैश्विक औद्योगिक और निवेश केंद्र बनाने के लिए दूरदर्शी एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नेतृत्व की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समभाव और समावेशी राजनीति के प्रतीक हैं तथा देश-विदेश में उनकी सकारात्मक और विकासोन्मुख छवि बनी हुई है। विशेष रूप से खाड़ी देशों और वैश्विक भारतीय समुदाय के बीच उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।

अरशद खान ने दावा किया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के उद्योगों और व्यापार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। साथ ही खाड़ी देशों समेत अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार तथा कौशल आधारित अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि निवेश, निर्यात और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने से उत्तर प्रदेश वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर नई पहचान स्थापित कर सकेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सौहार्द और समावेशी विकास की पक्षधर रही है।

अंत में अरशद खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक और व्यापारिक शक्ति बनाने के लिए समावेशी सोच और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में दिखाई देती है।

सिपाह रेलवे क्रॉसिंग के पास गांजा बिक्री का वीडियो वायरल, प्रशासन पर उठे सवाल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास कथित रूप से गांजा बिक्री और खुलेआम नशा सेवन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में सड़क किनारे एक गुमटी पर कुछ लोग बेखौफ होकर गांजे का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त स्थान पर लंबे समय से अवैध नशे का कारोबार चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

वायरल वीडियो में कथित तौर पर नशे की बिक्री और सेवन खुलेआम होता दिखाई दे रहा है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश भी देखा जा रहा है।

हालांकि, इस मामले में अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं, लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

सोने की खरीद को लेकर IBJA ने की संयम बरतने की अपील

अभिताश गुप्ता

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने की खरीद को लेकर दिए गए बयान के बाद इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने ज्वेलर्स और ग्राहकों दोनों से संयम बरतने की अपील की है। IBJA के जौनपुर जिला सेक्रेटरी मधुसूदन बैंकर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री ने कहीं भी दुकानें बंद करने या स्वणार्भूषणों की बिक्री रोकने की बात नहीं कही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आशय केवल इतना है कि देश वर्तमान परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए लोग जरूरत के अनुसार ही सोने की खरीद करें और जहां संभव हो पुराने सोने को रीसायकल या रिपॉलिश कराकर उपयोग में लाएं। IBJA ने ज्वेलर्स से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की घबराहट में न आएं और अपना व्यापार सामान्य रूप से जारी रखें।

संगठन ने कहा कि सरकार के पास इस विषय को लेकर कोई बड़ा रोडमैप हो सकता है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। फिलहाल संगठन किसी आंदोलन, बाजार बंदी या उग्र प्रदर्शन के पक्ष में नहीं है। जल्द ही विभिन्न एजेंसियों से चर्चा के बाद स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

IBJA ने ग्राहकों से भी अपील की है कि वे जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। संगठन का कहना है कि भारत को सोना विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर असर पड़ता है। ऐसे में पुराने सोने को रीसायकल कर नए आभूषण बनवाना बेहतर विकल्प हो सकता है।

जौनपुर सरार्फा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा बड़े स्तर पर सोने के भंडारण और निवेश को नियंत्रित करने की है। वहीं एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष विनोद सेठ ने ज्वेलर्स बंधुओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव को दी अंतिम श्रद्धांजलि

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा नेता अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर फैल गई है। मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कई राजनीतिक दलों के नेता और समर्थक भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रतीक यादव लंबे समय से अस्वस्थ बताए जा रहे थे। उनका अंतिम संस्कार पारिवारिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाएगा। प्रतीक यादव की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे मौत हुई।

प्रतीक यादव के निधन से राजनीतिक जगत में शोक

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई एवं भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह मात्र 38 वर्ष के थे। उनके अचानक निधन की खबर से यादव परिवार सहित राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। परिजन उन्हें तत्काल लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता के मुताबिक सुबह करीब 5:55 बजे प्रतीक यादव ने अंतिम सांस ली। सूत्रों के अनुसार प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके फेफड़ों में क्लॉट की समस्या बताई जा रही थी और उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। कुछ दिन पहले भी उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निधन के समय अपर्णा यादव दिल्ली में थीं और सूचना मिलते ही लखनऊ के लिए रवाना हो गईं। परिवार के अन्य सदस्य भी आवास पहुंच रहे हैं। प्रतीक यादव, पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। प्रतीक यादव के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदना जताई है।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर बरेका केंद्रीय चिकित्सालय में भव्य समारोह आयोजित

जनपद में हमारी नर्सें हमारा भविष्य- शसक्त नर्सें जीवन बचाती हैं' थीम पर नर्सिंग स्टाफ ने ली सेवा की शपथ

वाराणसी(उत्तरशक्ति)। बनारस रेल इंजन कारखाना के केंद्रीय चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महाप्रबंधक आशुतोष पंत के दिशा-निर्देशन और प्रमुख मुख्य चिकित्साधिकारी देवेश कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ।कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी लालजी चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सा कर्मियों ने कैंडिल लाइट के साथ शपथ ली कि वे समर्पण, सेवाभाव और मेहनत के साथ रोगियों की बेहतर सेवा करेंगे। मुख्य अतिथि लालजी चौधरी ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विचार और कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए सभी चिकित्सा कर्मियों को पूर्ण लगन के साथ मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया।प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेश कुमार ने इस वर्ष की थीम 'हमारी नर्सें हमारा भविष्य- शसक्त नर्सें जीवन बचाती हैं" पर

विचार व्यक्त करते हुए नर्सों के प्रति सम्मान और आभार जताया। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नर्सों के योगदान का स्मरण कराया और मरीजों की बेहतर देखभाल, दवाइयों का प्रबंधन तथा इमरजेंसी के दौरान पूर्ण लगन और सेवा भाव से कार्य करने का आह्वान किया।समारोह में वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी और प्रसूति रोग विशेषज्ञ मधुलिका सिंह, वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी और फिजिशियन एस के मौर्या, वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी और फिजिशियन मिन्हाज अहमद ने अपने विचार रखे।

सौरभ सागर ने स्वरचित कविता पाठ कर नर्सों के योगदान पर प्रकाश डाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रवक्ता पूनम सिंह ने नर्सों के बेहतर वर्क लाइफ संतुलन पर ध्यान देते हुए सेवा में मजबूती से लगे रहने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में विशाल मिश्रा, सौरभ, अब्दुल माबूद, हिमांशु रंजन, आरजू खर्रे, अमित गुप्ता, गौरव सिंह, प्रेक्षा पांडेय, मुख्य नर्सिंग अधीक्षक चंद्रकला राव, सीता कुमारी सिंह, कमला श्रीनिवासन, उषा सिंह, अनीता चंद्रा, आरती, एलीश कुजूर, उषा जैसल, संजू लता गौतम, कंचन मणि, वर्षा शर्मा, परम हंश मीना, सुप्रिया, ज्योति सिन्हा, प्रीती, अनीता पटेल, दीपशिखा पटेल सहित बड़ी संख्या में चिकित्साकर्मी उपस्थित रहे।

तेज रफ्तार अर्टिगा ने मचाया कहर, बोलेरो नाले में गिरी, कई घायल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के वी मार्ट पुलिया के पास बुधवार को तेज रफ्तार अर्टिगा कार के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में बोलेरो वाहन करीब 15 फीट नीचे नाले में जा गिरा, जबकि कई लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, तेज गति से आ रही अर्टिगा कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर बोलेरो वाहन से जा भिड़ी। जोरदार टक्कर के बाद बोलेरो सड़क किनारे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार एक महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। वहीं अर्टिगा कार में सवार चार लोग भी चोटिल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। प्राथमिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

सीबीएसई इंटरमीडिएट परीक्षा में अरिहंत यादव ने प्रथम श्रेणी प्राप्त कर बढ़ाया मान

डॉ. इम्तियाज अहमद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में अरिहंत यादव ने प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल कर परिवार एवं क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही परिजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अरिहंत यादव की इस सफलता को उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं गुरुजनों के मार्गदर्शन का परिणाम माना जा रहा है। परिजनों ने बताया कि अरिहंत शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर एवं मेहनती रहे हैं, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। इस उपलब्धि पर शुभचिंतकों एवं वरिष्ठजनों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं परिवारजनों ने सभी के स्नेह एवं आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। अरिहंत यादव उत्तरशक्ति हिन्दी दैनिक परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

भूमि पैमाइश के 1800 मामले लंबित: प्रषासन सख्त

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भूमि पैमाइश और पत्थरगड्डी के 1800 से अधिक लंबित मामलों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने सभी आवेदनों का निस्तारण जून माह तक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तहसील स्तर पर भूमि पैमाइश में देरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। धारा 24 के तहत हकबंदी के लिए सभी छह तहसीलों में 1800 से अधिक आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। मई और जून में खेत खाली रहते हैं, इस अवधि का लाभ उठाते हुए अभियान चलाकर पैमाइश और पत्थरगड्डी के लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट ने बताया कि लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए संबंधित तहसीलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि भूमि पैमाइश के लंबित आवेदनों को लेकर अब कोई बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रत्येक सप्ताह इसकी अलग से समीक्षा की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कर्मियों के निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है तहसीलवार लंबित आवेदनों की संख्या इस प्रकार है मछलीशहर में 458, केराकत में 480, मड़ियाहूं में 400, बदलापुर में 350 और सदर तहसील में 139 आवेदन लंबित हैं। हालांकि, कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लंबित रहते हैं, लेकिन विभाग रहित आवेदनों की भी समय पर सुनवाई न होने से समस्या और गंभीर हो रही है।

स्नेहा दुबे पंडित ने स्थानीय नागरिकों के साथ की बैठक

बापने, वसई। कामन-बापने रोड प्रोजेक्ट के तहत पालनापाड़ा क्षेत्र में मंदिर और मैदान प्रभावित होने की आशंका को लेकर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा एक प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) दिया गया था। इसी संदर्भ में आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे एवं स्थानीय नागरिकों के साथ क्षेत्र का फिजिकल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को पालनापाड़ा स्थित मंदिर और मैदान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुल क्षेत्र एवं कोल्ही स्थित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यालय की खतरनाक स्थिति को देखते हुए वहां विकास कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में स्थानीय नागरिकों की भावनाओं, धार्मिक स्थलों के महत्व तथा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

इस अवसर पर वसई-विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे, वार्ड कमेटी जी के जूनियर इंजीनियर अनिकेत मोहिते, हरिहर पाटिल, केदारनाथ म्हात्रे, भाजपा जिला सचिव प्रवीण गावडे, पोमन ग्राम पंचायत के सरपंच आत्माराम ठाकरे, वसई ईस्ट साउथ मंडल के महासचिव चंद्रेश कुलकर्णी, दिनेश म्हात्रे, नवशी वाघ, हेमंत बरा, दमयंती निबारे, आकाश गायकवाड़, मयंक शेठ, कल्पेश पांडे सहित स्थानीय नागरिक, श्रमजीवी संघ के पदाधिकारी एवं भाजपा के पदाधिकारी-कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी विवेकानंद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी ओमप्रकाश बैरिया को चेतगंज पुलिस ने मंगलवार शाम गिरफ्तार किया। मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के भुल्लनपुर निवासी आरोपी की पत्नी भीम आर्मी की वाराणसी अध्यक्ष है। पत्नी के मोबाइल से ओमप्रकाश ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया।

चेतगंज इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने सुबह प्राथमिकी दर्ज कराई कि आरोपी ओमप्रकाश बैरिया ने फेसबुक पर स्वामी विवेकानंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया है। पोस्ट के माध्यम से स्वामी विवेकानंद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पैर से प्रहार करते दर्शाया गया है, जिससे असंख्य लोगों की धार्मिक, सामाजिक और वैचारिक भावनाएं आहत हो रही हैं।

लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना हेतु जनप्रतिनिधियों संग बैठक संपन्न

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना हेतु बैठक राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव , सांसद मछलीशहर सुश्री प्रिया सरोज, विधायक बदलापुर रमेश चंद्र मिश्र, शाहगंज रमेश सिंह, जफराबाद जगदीश नारायण राय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के द्वारा जनप्रतिनिधिगणों को अवगत कराया गया कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर से प्राप्त अनुमोदन को जनप्रतिनिधियों के सूचनार्थ पुस्तिका रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल कार्यो की संख्या 331 एवं लागत रु0 575.67 करोड़ है।

मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया द्वारा जनप्रतिनिधिगणों से वर्ष 2026-27 हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधानसभावार कार्ययोजना गठित कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उन्होंने समस्त जनप्रतिनिधिगण से विधानसभा से संबंधित लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनांतर्गत कार्य हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता क्षेत्रवार संबंधित जनप्रतिनिधिगण से व्यक्तिगत संपर्क करके विलंबत्तम एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य योजना गठित करते हुए शासन को प्रेषित करें। बैठक में जनप्रतिनिधिगण द्वारा लगभग 450 प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए और सदन द्वारा एकमत से प्रस्तावित किया गया कि एक सप्ताह के भीतर अन्य प्रस्ताव संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा संपर्क करने पर उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा।जिलाधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधिगण को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई। बैठक में परियोजना निदेशक के.के. पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता लोक लोक निर्माण विभाग एस०के० सिंह, के साथ लोक निर्माण विभाग का समस्त स्टाफ और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जौनपुर: गोलीकांड में घायल प्रेमचंद यादव ने तोड़ा दम, गांव में पसरा मातम

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जाफराबाद थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव निवासी जन सेवा केंद्र संचालक प्रेमचंद यादव का वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान निधन हो गया। करीब दो महीने पहले बदमाशों द्वारा गोली मारे जाने के बाद से वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। बताया जाता है कि 11 मार्च 2026 की रात प्रेमचंद यादव जन सेवा केंद्र बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने उन्हें रोककर लूटपाट का प्रयास किया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। करीब दो महीने तक चले इलाज के बाद बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। निधन की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने बताया कि इलाज में परिवार की पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

बहराइच के बाद खेतासराय के गाजीमियां के मेले पर लगा प्रतिबंध

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रदेश शासन द्वारा बहराइच और संभल के बाद अब जौनपुर के खेतासराय में लगने वाले सैयद सालार मसूद गाजी मियां मेले पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 14 मई को प्रस्तावित इस मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं।

खेतासराय थाना क्षेत्र में मेला स्थल पर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का मेला, झूला, सर्कस, चरखी अथवा अस्थाई दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। पुलिस लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और बाहर से आने वाले दुकानदारों को वापस भेजा जा रहा है।

शासन के निर्देश के बाद जौनपुर पुलिस और एलआईयू की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं। मेला आयोजन से जुड़े मुजावरों और दफालियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की सख्ती के चलते आयोजन से जुड़े लोग खुलकर सामने आने से बच रहे हैं।

शाहगंज के क्षेत्राधिकारी गिरेन्द्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस बार मेले की अनुमति नहीं दी गई है। यदि कोई बिना अनुमति आयोजन करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बताया जाता है कि खेतासराय में गाजी मियां का मेला वर्षों पुरानी परंपरा के तहत आयोजित होता रहा है, जिसमें पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से हजारों लोग पहुंचते थे। जरूरी है फोटो ी साथ हालांकि इस बार प्रदेश सरकार के सख्त रुख और सुरक्षा कारणों के चलते आयोजन पर रोक लगा दी गई है।

जिला प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

मुंबई। नासिक में आयोजित होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कुंभ मेले के आधिकारिक निशान (लोगो) का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु-संतों और महंतों के साथ चर्चा कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। सरकार की ओर से कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं प्रस्तुत की गईं। सरकार ने बताया कि कुंभ मेले के लिए कुल 377 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इनमें से 94 एकड़ भूमि को नासिक महानगरपालिका द्वारा अधिग्रहित किया जा चुका है, जबकि शेष 283 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 2267 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। बैठक में यह आश्वासन भी दिया गया कि अखाड़ों की जमीन अधिग्रहित करते समय उचित मुआवजा अथवा वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रत्येक बड़े अखाड़े को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये तथा छोटे संस्थानों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की ओर से यह भी घोषणा की गई कि कुंभ मेला प्राधिकरण अखाड़ों के बिजली बिलों का भुगतान करेगा। मानसून के दौरान साधु-संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेन बसेरा की व्यवस्था भी की जाएगी। करीब 1450 एकड़ क्षेत्र में विशाल साधुग्राम विकसित किया जाएगा। स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 हजार स्वच्छता मित्र तैनात किए जाएंगे। सरकार ने गोदावरी नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में सड़क, पार्किंग, पेयजल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल, आपदा प्रबंधन, महिलाओं एवं दिव्यांगों की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कुंभ मेले के आयोजन में फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

वसई ईस्ट में चिंचोटी, कामन व अंजुरफाटा रोड का निरीक्षण

वसई रोड। स्नेहा दुबे पंडित ने चिंचोटीझकामनझअंजुरफाटा रोड, वसई ईस्ट का दौरा कर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। विधानसभा के नागपुर सत्र से लेकर अब तक लगातार इस सड़क परियोजना का फॉलोअप किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सड़क की मौजूदा स्थिति, कार्य की प्रगति और नागरिक सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि चिंचोटी नाका से कामन तक सड़क के एक हिस्से पर कंक्रीटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं कामन से नागले तक सड़क के एक तरफ निर्माण कार्य जारी है, जबकि दूसरी तरफ सड़क की हालत बेहद खराब होने से रिक्शा और मोटरसाइकिल चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून से पहले कंक्रीटिंग का कार्य पूरा होना संभव नहीं होने के कारण विधायक ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिए कि बरसात के दौरान राहत देने के लिए सड़क के खराब हिस्से का अस्थायी डामरीकरण किया जाए। इससे स्थानीय नागरिकों और इंडस्ट्रियल एस्टेट में आने-जाने वाले लोगों को मानसून के दौरान कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्र में लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान प्रशासन ने भविष्य में लोगों को अधिक सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

निरीक्षण के मौके पर विधायक स्नेहा दुबे पंडित के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

पीएम के आह्वान पर इंदौर महापौर पुष्यमित्र का ऐलान: हफ्ते में एक दिनकरेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल

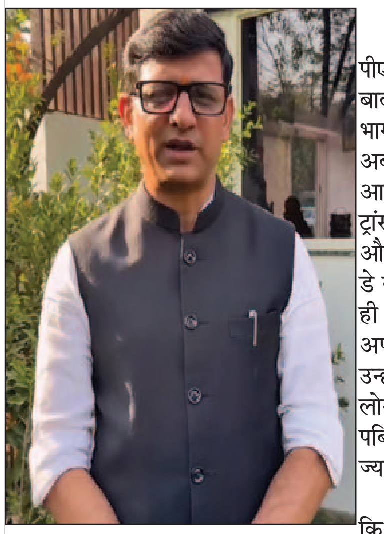

प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तर शक्ति)। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक ऐलान किया है। अब वे भी हफ्ते में एक दिन आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और हफ्ते में एक दिन नो कार डे को फॉलो करेंगे।इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी यहीं अपील की है। इसे लेकर उन्होंने वीडियो के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ।

महापौर पुष्यमित्र ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की चिंता करते हुए देश की जनता से ईवी के प्रयोग का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग का और डीजल-पेट्रोल की कम खपत का आह्वान किया है। इंदौर जिसे पीएम ने एक दौर कहा है एक बार फिर इस बात को सिद्ध करता है कि पिछले तीन सालों से लगातार इंदौर पूरे देश को नो कार डे के माध्यम से इसी तरह का संदेश देते आया है। जनता से अपील है कि हफ्ते में एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें । यह जानकारी दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ प्रणित नरेंद्र तिवारी ने दी है।

रक्षा को लेकर हिंदुस्तान यूनाइटेड मोर्चा का बड़ा ऐलान, आंदोलन की चेतावनी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। तंदूरी दरबार में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिंदुस्तान यूनाइटेड मोर्चा ने गौ रक्षा के मुद्दे को लेकर बड़ा और आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन के अध्यक्ष आरिफ खान और उपाध्यक्ष शहनवाज मंजूर ने कहा कि अब यह अभियान केवल अपील तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनशक्ति के साथ सड़क पर उतरकर निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी।

अध्यक्ष आरिफ खान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गौ रक्षा का मुद्दा अब टालने योग्य नहीं है। यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए, तो हिंदुस्तान यूनाइटेड मोर्चा पूरे प्रदेश में व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने मुस्लिम समाज से भी आगे आकर गौ संरक्षण के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि गौ रक्षा इंसानियत, करुणा और साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, इसे किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल कागजों पर योजनाएं बनाई जा रही हैं, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जनता अब जवाब चाहती है और संगठन उनकी आवाज को बुलंद करेगा।

उपाध्यक्ष शहनवाज मंजूर ने पश्चिम बंगाल और असम सरकारों पर हमला बोलते हुए इन राज्यों में गौ हत्या और मांस सेवन पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकारें इस दिशा में कार्रवाई नहीं करतीं, तो उनकी मंशा पर सवाल खड़े होंगे।

पत्रकार वार्ता में संगठन ने यह भी घोषणा की कि 15 मई को दोपहर 2 बजे सिपाह चौराहे पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आगमन पर संस्था द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को गौ संरक्षण से जुड़ी छह प्रमुख मांगों वाला ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।

ज्ञापन में गाय को ह्राष्ट्रमाताह्व घोषित करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने, उत्तर प्रदेश में गाय को ह्राजकीय माताह्व घोषित करने, सभी गौशालाओं में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने, प्रत्येक जिले में आधुनिक गो-चिकित्सालय स्थापित करने, घायल गायों के लिए 108 जैसी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने तथा मृत गायों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए स्पष्ट सरकारी नीति बनाए जाने की मांग शामिल है।

संगठन पदाधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले समय में यह मुद्दा प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। अंत में अध्यक्ष आरिफ खान और उपाध्यक्ष शहनवाज मंजूर ने संयुक्त रूप से कहा कि यह लड़ाई जनभावनाओं से जुड़ी है और इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।

बरात से लौट रही पिकअप पलटी, दो की मौत

बलिया (उत्तरशक्ति)। रामपुर बरकोनिया एसओ की विनोद यादव ने बताया कि मिजार्पुर जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के चुनरी बांध पुरवा निवासी शिवकुमार के बेटे अजय गोंड की शादी रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के चेनरी टोला निवासी विक्रम की बेटी से तय थी। मंगलवार की रात करीब 10 बजे बरात चेनरी टोला आ रही थी। कठार गांव के पास तेज घुमावदार मोड़ पर बरातियों से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। पिकअप में सवार बरातियों को बाहर निकालकर चतरा पीएचसी पहुंचाया गया। घायलों में आशीष, गोलू, रामाशीष, श्याम सुंदर, रामजनम, आकाश, रामसुंदर, बिहारी, रोहित सहित 15 लोग हैं।